

गृह मंत्री जी से आप्रह कहंगा कि वे हनुमंतराय जी के केस पर भी विचार करें।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): That is a Naxalite area. Therefore, there is need to provide security there and the Government must do something about it.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): मैडम, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से आप्रह है कि वे हनुमंतराय जी की भी सुरक्षा की व्यवस्था करें।

उपसभापति: ठीक है, रेणुका जी की सुरक्षा का प्रश्न भी हल हो गया और हनुमंतराय जी की सुरक्षा का भी प्रश्न हल हो गया, दोनों का काम हो गया और अब सभी खुश हो गए। श्री आनन्द प्रकाश गौतम।

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र): मैडम, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन चल रहा है और सरकार की पूरी मंत्रि परिषद की ओर से अकेले खरार खरमर साहब यहाँ बैठे हैं।

SHRI V. NARAYANASAMY: What about security for Mr. Hanumantha Rao?

THE DEPUTY CHAIRMAN: He will do it. I will see that it is done for both.

श्री प्रमोद महाजन: मैडम, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उनको निर्दे दें कि वह भी सदन से चले जाएं ताकि बाकी जो सदस्य हैं, वह आपसे चर्चा कर लें। यहाँ कम-से-कम एक कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर को आप अगर जीरो-खरार में नहीं रखेंगे तो आप कितनी गंभीरता से उठाए जाने वाले मामलों को लेंगे?

उपसभापति: गुलाम नबी आजाद साहब आ गए हैं।

SHRI SIKANDER BAKHT: It is not enough that only during Zero Hour, a Cabinet Minister should be here. As long as the House sits, there has to be a Cabinet Minister here, and it is not the first time that we have raised this matter.

वित्त मंत्रालय एवं संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वज्रर खन्ना): मैडम, लोकसभा के वंशर कोटिंग थी, इसलिए जो माननीय मंत्री यहाँ थे वह कोटिंग... (व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Abrar Ahmed, I am sorry. This is no explanation.

SHRI SIKANDER BAKHT: Don't take the House for granted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Sikander Bakht Sahab, please. This is no explanation and I am not going to accept it, because if there was

voting in the Lok Sabha, there are many Ministers who belong to Rajya Sabha and they have no business to vote there. They should be here. So, that is no explanation. If they are busy in some business in the other House, we accept it. If they are busy somewhere in some meeting, we accept it. But not for voting. So please find another excuse.

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): When the voting is there, the Ministers have to be there because the Members tend to run away and the Ministers are required to bring them back.

RE-INORDINATE DELAY IN PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE TO SOME S/C, S/T FAMILIES

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now Shri A. P. Gautam.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान एक ऐसे मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जिससे कि अनुसूचित-जाति व जनजाति के सेकड़ों परिवारों की जीविका का प्रश्न जुड़ा हुआ है।

महोदय, अनुसूचित-जाति व जनजाति के लोगों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए लगभग एक साल से ज्यादा हो रहा है, छह सौ पचहत्तर लोगों को दिल्ली प्रशासन द्वारा एस०टी०ए० बस परमिट स्वीकृत किए गए थे, रेट-लाइन बसों के परमिट उन्हें दिए गए थे और सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 95 प्रतिशत आर्थिक सहायता, 4 प्रतिशत के श्रृंखले के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी जिससे कि वे बसों को खरीद सकें और अपनी जीविका अर्जित कर सकें।

इस मद में भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त विकास निगम दिल्ली को कुल भिनाकर 25 करोड़ रुपये का आबन्धन किया गया था, परन्तु खेद है कि दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम ने केवल 9 करोड़ रुपये का ही श्रृंखला बांटा और इसमें गंभीर मसला यह है कि 15.8 करोड़ रुपये 16 करोड़ रुपये उस विकास निगम ने एक ऐसे बुरे के मामले में लगा दिया, जिसके बारे में माननीय सदन में कई बार पूरी सरकार को कलंकित किया गया। वह ऐसा केवल व्याज कमाने के लिए, काफी धन कमाने के लिए उसमें लगा दिया गया क्योंकि उसमें 22 परसेंट व्याज देने को कहा गया था।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से केवल वहाँ से 100 लोगों को ही श्रृंखला उपलब्ध कराया जा सका और बाकी सभी लोगों को जिन्होंने श्रृंखला के लिए प्रार्थना पत्र दिये थे,

आज भी अंगुण उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, जिसके लिए वह लोग साल भर से परेशान हैं। उनको हर तीन महीने के लिए परमिट सेंक्सन होता है, तीन महीने के बाद उनके परमिट खतम होने की घण्टी बजा दी जाती है और फिर तीन महीने के बाद हाथ पैर जोड़ते हैं तो तीन महीने के लिए और परमिट मिल जाता है। अब 30 सितंबर उनके परमिट की आखरी तारीख है। अगर उस समय तक उनको अंगुण उपलब्ध नहीं हुआ, वह बस नहीं खरीदते हैं तो वह सारे के सारे 150 परमिट समाप्त कर दिए जाएंगे और उन सभी परिवारों की स्थिति यह हो जाएगी कि उनकी जीविका के लाले पड़ने लगेंगे।

महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कठना चाहता हूँ और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आप उन बंदूकों को, जिनको इस आवासन पर परमिट दिए गए थे, उनको आप अंगुण दिलाएं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनके आप अंगुण दिलाने की स्थिति में हैं क्योंकि भारत सरकार ने जिनको अंगुण उपलब्ध कराने के लिए धन आवंटित किया था उन्होंने बजाय इसके कि अनुसूचित जाति के लोगों को अंगुण उपलब्ध कराया जाता उसको ब्याज कमाने में लगा दिया, शेरार घोटाले में लगा दिया। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, इस प्रकार से जो अनुसूचित जाति के अंगुण के लिए धन आवंटित हो और उसको ब्याज कमाने के लिए या दूसरे शेरार घोटाले के लिए कोई लगा दे तो उसके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की जा सकेगी? क्या आप उनको अंगुण उपलब्ध करा सकेगी? अनुसूचित जाति, जनजाति के हितों को रौंद कर जिस संस्था ने या जिस वित्त विकास निगम ने धन का दुरुपयोग किया है उसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे?

महोदया, इसी के साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इस सबका क्या असर पड़ा है। पिछले साल जिस मई में 25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था और वित्त विकास निगम की ओर से केवल 9 करोड़ रुपये ही उपभोग किया जा सका था, उसका नतीजा यह हुआ कि इस वर्ष केवल उसको ऐसे मर्चों में 10 करोड़ रुपये ही आवंटित किया गया है क्योंकि उनका यह लक्ष्य था कि आपने खर्च ही नहीं किया, आपको अक्षरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे हितों को कुचला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि या तो सरकार में कहीं हज्जा शक्ति की कमी है या सरकार के हथारे पर ऐसा किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ इस संस्था के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही की गई है या नहीं की गई है? आप इन लोगों को 30 सितंबर तक अंगुण दिला पाएंगे या फिर इन लगभग दूई सौ परिवारों को मूख के कगार पर धकेलने के लिए तैयार हैं? मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ।

श्री जह्मदेव जामन्य पासवान (बिहार) : मैडम, मैं इससे संभव करता हूँ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Before we proceed further, I would like to inform hon.

Members that Friday will be the last day of this Session, hopefully. Tomorrow, perhaps, we will have a calling-attention motion. So, there will be no Special Mentions. Keeping that in view, I have allowed a large number of Special Mentions today as the Members are worried about various issues. Keeping all these things in view, I request hon. Members that today we dispense with the lunch hour and we finish this so that we can have the discussion on the Appropriation Bills, if the House so agrees. So, there will be no lunch hour. Agreed. Shri Shastri.

RE. DEMAND FOR CONSENSUS ON THE PROBLEM OF BANGLADESHI INFILTRATORS LIVING IN INDIA

श्री विष्णु काम्ल शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : माननीय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का और इस माननीय सदन का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर समस्या की ओर आकृष्ट कर रहा हूँ। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात बार-बार इस सदन में उठी है, लेकिन अभी दिल्ली के एक विख्यात दैनिक "आगरा" ने कई महत्वपूर्ण साक्षात्कार प्रकाशित किए हैं और उनमें से एक साक्षात्कार दिल्ली के उपराज्यपाल श्री पी. के. इमे का है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि दिल्ली में बसे हुए बांग्लादेशियों को बाहर न निकाल पाने का एक कारण अन्तराष्ट्रीय दबाव है। यह बहुत ही चिंताजनक बात है। अगर किसी अन्तराष्ट्रीय दबाव के कारण बांग्लादेशियों की आपसी की कोई ठोस योजना दिल्ली में भारत सरकार नहीं बना सकती तो हमको यह जानने का अधिकार है कि वे कौन से देश हैं जो हम पर यह दबाव डाल रहे हैं। इसी तरह जो सूसी बड़ी बात दिल्ली के पुलिस आपुक्त श्री कौशल ने स्वीकार की है कि — हाँ, यह ठीक है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए कानून-व्यवस्था के लिए समस्या बन गए हैं। लेकिन उन्होंने यह कहा है कि सरकार की कोई नीति स्पष्ट न होने के कारण हम उनके खिलाफ कोई प्रभावी कदम नहीं उठा सकते। उन्होंने यह भी कहा है कि जम्मूगिरपुरी में जब उन्होंने कदम उठाया और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने प्रतिवाद किया, तो उसके बाद बहुत सी मानव अधिकार संस्थाओं ने तथा बहुत से राजनीतिक बलों ने इसका प्रतिवाद किया। इसलिए वह कदम नहीं उठा सकते। उन्होंने यह भी बताया कि वह बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली छोड़कर पास के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, लोनी और नोयडा में चले गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कौन सी संस्थाएँ हैं जो इस राष्ट्रीय प्रश्न पर भी बारबार आपत्ति करती हैं। तीसरे, खबर है कि घुसपैठियों पर सवा दो लाख रुपये यानी सवा दो सौ करोड़ रुपये प्रति माह भारत को खर्च करना पड़ता है। उपसमापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस दिशा में कोई स्पष्ट नीति